(e) Monthwise details are as under:-

Month	*Quantity demanded*
	(in MTs.)
Janaurary, 1990	63.164
February, 1990	23.940
March, 1990	43.934
April, 1990	51.886
May, 1990	122.270
June, 1990	109.050
July, 1990	101.170

(f) and (g) Do not arise as supplies are being made.

Commitments for Development of Agriculture

590. SHRI SYED SIBTEY RAZI. Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state

(a) whether Government are committed to maintain parity of prices between agricultural and industrial produce,

(b) whether commitment is also to encourage the cultivation of pulses, oilseeds, fruits, nuts and other cash crops;

(c) whether commitment is also to restructure the Agricultural Cost and Price Commission to give two-thirds representation to farming community,

(d) if so, the details thereof,

(e) whether Government have taken any steps so far to implement these commitments, and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR) (a) It is the endeavour of the Government to ensure that terms of trade between agricultural and non-agricultural sectors do not go against the farming sector.

(b) Yes, Sir.

(c) No decision has been taken to restructure the Commission on Agricultural Costs & Prices, giving two-thirds representation to farming community.

(d) Does not arise.

(e) and (f) (i) The Expert Committee set up to review, *inter-alia*, the terms of trade between agricultural and non-agricultural sectors and suggest methods to safeguard the interests of farmers, has submitted its final report. The report is under the consideration of the Government.

(ii) To encourage the production of pulses, oilseeds and other cash crops several Central Sector, Centrally sponsored and State schemes are being implemented.

मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि

591 **श्री बलराम सिंह यादव:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रिलेंटलेस राइज इन प्राइसेज" (मूल्यों में लगातार वृद्धि) शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष मार्च से लेकर जून तक की लगभग 26 सप्ताहों की अवधि में आम उपभोक्ता वस्तुओं के थोक मूल्यों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है,

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वर्तमान में सरकार द्वारा मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए कतिपय उपाय किए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए जाने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य

मंत्री(श्री राम पूजन पटेल): (क) और (ख) जी, हां, तथापि, 31-3-90 से 30-6-90 तक केवल 13 सप्ताह ही होते हैं। इस अवधि में, आवश्यक वस्तुओं में थोक मूल्य सूचकांकों में मिश्रित **रुख** देखा गया है। 30 जून, 1990 को समाप्त हुए 26 सप्ताहों के दौरान और 13 सप्ताहों के दौरान, तथा 1989 में तदनुरूप अवधि के दौरान चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत उतार-चढ़ाव दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के रुख पर नियंत्रण करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह के उपाय किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए उपायों में मोटे तौर पर ये उपाय शामिल हैं: आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना; खाद्यान्नों की कारगर वसूली और उनका सुरक्षित भंडार रखना; सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना; **मूल्यों और उपलभ्यता स्थिति की परिवीक्षा करना;** आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों और अन्य नियामक उपायों को कड़ाई से लागू करना, मूल्यों में असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए जहाँ भी जरूरत हो, आयात के जरिए देशीय आपूर्ति को बढ़ाना। व्यापक बृहत-आर्थिक मोर्चे पर किए गए उपायों के अतिरिक्त सरकार द्वारा खाद्य तेलों, दालों, चाय, चीनी और सीमेंट इत्यादि जैसी विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं, जिन पर दबाव है, के संबंध में विशेष उपाय भी किए गए हैं।

विवरण

30.6.1990 को समाप्त 26 सप्ताहों, 13 सप्ताहों तथा 1989 में तदनुरूप अवधि के दौरान चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत उतार-चढ़ाव दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

वस्तु	प्रतिशत उतार-चढ़ाव			
	30.6.1990 / 31.12.1989	1.7.1989 / 31.12.1988	30.6.1990 / 31.3.1990	30.6.1989 / 1.4.1989
	1	2	3	4
चावल	+6.0	+8.9	+5.6	+4.0
गेहूं	+3.9	−13.2	+13.3	−9.1
ज्वार	−7.9	+13.6	+0.8	+5.1
बाजरा	+10.4	+3.6	+17.5	+4.4
चना	+12.1	−12.3	+12.0	+4.1
अरहर	+19 5	+14.6	+6.7	+24.4
मूंग	+12.6	+1.3	+2.5	+1.3
मसूर	+0.3	−5.2	+0.4	+0.1
उड़द	+5 1	+9.4	−0.4	+17.9
आलू	+89.5	+57.7	+66.0	+74.9
प्याज	+23.8	−49.0	+38.2	−6.0
दूध	+5.2	+3.6	+1 9	+7.9
मछली	+14.3	+10 8	+4 3	+8.8
मटन	+4.5	+4.6	+1.7	+1.5

1	2	3	4	5
लाल मिर्च	—10.9	—42.5	—5.4	+7.9
चीनी	+1.7	+10.1	—0.8	+5.7
गुड़	+23.5	+48.0	+15.2	+23.5
नमक	+0.4	+13.4	—0.4	+12.7
आटा	—3.2	+5.9	+3.9	—2.9
मिट्टी का तेल	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
वनस्पति	+13.6	+0.1	+7.6	+3.9
जिंजली का तेल	+28.3	+14.1	+2.8	+6.6
सरसों का तेल	+29.2	-9.9	+23.1	—1.7
नारियल का तेल	+5.2	—23.8	+3.7	—4.3
मूंगफली का तेल	+33.9	+9.5	+13.8	+15.4
वाय	+15.3	+32.9	+16.2	+18.3
सूती कपड़ा (मिल का)	+0.3	+7.1	—0.3	+1.2
नहाने का साबुन	+2.5	+0.7	+2.5	स्थिर
दियासलाइयां	स्थिर	+0.1	स्थिर	स्थिर

खाद्य तेलों की पूर्ति और उत्पादन

592. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1989-90 के दौरान देश में खाद्य तेलों की पूर्ति तथा खपत में भारी अंतर होने की संभावना है; यदि हां, तो इस वर्ष के लिए सरकार द्वारा इस मद की मांग और पूर्ति की कितनी मात्रा आंकी गई है;

(ख) क्या सरकार ने खाद्य तेल का आयात करके मांग और पूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने खाद्य तेल के स्थान पर खाद्य तिलहनों का आयात करने की सम्भावनाओं पर विचार किया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री राम पूजन पटेल): (क) जी, हां। तेल वर्ष 1989-90 के दौरान खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति क्रमशः 57.72 लाख मी० टन तथा 47.81 लाख मी० टन आंकलित की गई है।

(ख) अंतर को पूरा करने के लिए खाद्य तेल का आयात, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के मूल्यों और देश में उपभोक्ताओं की पसन्द को ध्यान में रखते हुए इस समय परिष्कृत विरजित और निगंधीकृत पामोलीन का आयात किया जा रहा है। इस तेल का संसाधन तेल भेजने वाले देश में ही करना अपेक्षित होता है। अतः फिलहाल तिलहनों का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम को राज सहायता

593. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम